



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1630]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10 2010/श्रावण 19, 1932

No. 1630]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2010/SHRAVANA 19, 1932

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2010

का.आ. 1941(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को तारीख 21-4-2009 को भेजे गए नोटिस के अनुसार प्रधान ग्रामोद्योग संस्थान, बिचपड़ी, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संस्थान कहा गया है) द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आयोग कहा गया है) को, 5,57,966 रुपए (पाँच लाख सत्तावन हजार नौ सौ छियासठ रुपए केवल) की राशि, जिसके अंतर्गत ब्याज और दण्ड ब्याज भी हैं, का भुगतान किया जाना था;

और खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम, 30 के उप-नियम (2) के अधीन यथाअपेक्षित, उक्त आयोग द्वारा उक्त संस्थान को तारीख 25 अप्रैल, 2008 को कारण बताओ सूचना तामिल कराई गई थी जिसमें उक्त संस्थान को यह निर्देश दिया गया था कि उक्त सूचना की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आयोग को पाँच लाख सत्तावन हजार नौ सौ छियासठ रुपए केवल की उक्त राशि का भुगतान कर दें, जिसके असफल रहने पर उक्त आयोग उक्त नियम के नियम, 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19ख के अधीन भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उक्त राशि वसूली करने की कार्यवाही करेगा;

और उक्त संस्थान ने नोटिस के अधीन मांगी गई उक्त रकम के संदाय करने के अपने दायित्व आयोग को देय 5,57,966 रुपए (पाँच लाख सत्तावन हजार नौ सौ छियासठ रुपए केवल) की राशि की भुगतान देयता का विरोध करते हुए आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिवेदन किया और उक्त आयोग के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका सं. 64645/08 दायर की;

और उक्त मामले पर सुनवाई करने के पश्चात् इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तारीख 15 दिसम्बर, 2008 के अपने आदेश के अधीन याचिकाकर्ता को एक मास की अवधि के भीतर केवल दो लाख चालीस हजार रुपए की मूल राशि जमा करने और उपयुक्त न्यायनिर्णयन के लिए आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को मामले से संबंधित एक अधिकरण गठित करने के मामले को अग्रपिछित करने के निर्देश के साथ याचिका का निपटान किया;

और याचिकाकर्ता ने दो लाख चालीस हजार रुपए केवल की उक्त राशि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को जमा कर दी है, जिसकी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तारीख 27-4-2009 को पुष्टि कर दी गई है।

अतः अब, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, प्रधान ग्रामोद्योग संस्थान, बिचपड़ी, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की देयताओं के भुगतान के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए एक व्यक्ति से गठित अधिकरण, अर्थात् श्री पी. एस. वर्मा, अवर सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 का गठन करती है।

2. यह अधिकरण, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र, किन्तु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं, प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त अधिकरण का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. सी-18019/8/2009-केवीआई-II]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2010

S.O. 1941(E).—Whereas, a sum of Rs. 5,57,966 (Rupees five lakh fifty seven thousand nine hundred sixty six only) including interest and penal interest as per notice served by Khadi and Village Industries Commission to the petitioner on 21-4-2009 was payable by the Pradhan Gramodyog Sansthan (hereinafter referred to as the said Sansthan), Bichpadi, Baghpat, Meerut, Uttar Pradesh to the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter referred to as the said Commission);

And whereas, as required under sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules) the said Commission caused notice dated the 25th April, 2008 served on the said Sansthan directing them to pay the said sum of rupees five lakh fifty seven thousand nine hundred sixty six only to the said Commission within thirty days from the receipt of the said notice failing which the said Commission will proceed to recover the same as arrears of land revenue under section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 read with sub-rule (2) of rule 30 of the said rules;

And whereas, the said Sansthan has disputed its liability to pay the said sum of Rs. 5,57,966 (Rupees five lakh fifty seven thousand nine hundred sixty six only) to the said Commission, represented to the Chief Executive Officer of the Commission and filed a writ petition bearing number 64645/08 before the Allahabad High Court against the said Commission challenging the liability to pay the amount as demanded under notice;

And whereas, after hearing of the said case, the Allahabad High Court disposed of the Writ Petition vide its order dated the 15th December, 2008, with a direction to the petitioner to deposit such principal amount of rupees two lakh forty thousand only within a period of one month and forwarding the matter by the Commission to the Central Government for formation of Tribunal and appropriate adjudication thereof;

And whereas the petitioner deposited the said amount of rupees two lakh forty thousand with the Khadi and Village Industries Commission as has been confirmed by Khadi and Village Industries Commission on 27-4-2009.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri P. S. Verma, Under Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhavan, New Delhi-110011, to decide the question on the payment of dues by Pradhan Gramodyog Sansthan, Bichpadi, Baghpat, Meerut, Uttar Pradesh to the Khadi and Village Industries Commission.

2. The Tribunal shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The headquarter of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F.No. C-18019/8/2009-KVI-II]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.